International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 4, May-June 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित मुद्दे और उनका समाधान

Rajesh Gupta

Assistant Professor in Political Science, Babu Shobha Ram Govt. Arts College, Alwar, Rajasthan, India

ABSTRACT

अंग्रेजों की फूट डालों और राज करो की निति के परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 को भारतपाक विभाजन के साथ पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इसके ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी. इससे पूर्व पाकिस्तान नाम कोई देश दुनिया में नही था. जिन्ना की स्वार्थी निति के चलते बीसवीं सदी के आरम्भ में ही मुसलमानों को लामबंद कर एक नये राष्ट्र पाकिस्तान के लिए मांग शुरू कर दी थी.भारत और पाकिस्तान में सम्बन्ध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनैतिक मुद्दों कि वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस रिश्ते का मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए है और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक समझौते व युद्ध कर चुके हैं। इन देशों में तनाव मौजूद है जबकि दोनों ही देश भारत के इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था से ज़ुड़े हुए हैं।पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत और पाक के मध्य रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव भी देखे गये, उरी और पठानकोट हमलें के समय दोनों देशों के रिश्तों पूरी तरह तल्ख हो चुके हैं.इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के राजयनिक सम्बंध भी बिगड़ गये हैं. हालांकि कोरोना महामारी में भारत ने अपने पड़ोसी देशों को फ्री वैक्सीन नीति के तहत पाकिस्तान को भी निशुल्क वैक्सीन दी गई.दोनों देशों के मध्य व्यापारिक रिश्ते पूरी तरफ ढप हैं. प्राणरक्षक दवाइयों के अतिरिक्त अन्य किसी तरह के उत्पादों पर आयात पर पाकिस्तान सरकार द्वारा पूरी तरह से रोक लगाई गई हैं.जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A की बर्खास्तगी और दो बड़े आतंकवादी हमलों के बाद दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं. आने वाले कुछ वर्षों में रिश्तों में सुधार देखे जा सकते हैं.दो संगे भाइयों की तरह एक ही देश के विभाजन से जन्में भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरुआत से ही कटुतापूर्ण रहे हैं. पाकिस्तान ने कश्मीर प-आर 22 अक्टूबर 1947 को आक्रमण कर, इस दुश्मनी के बीज बो दिए था. भारत के जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने अन्यायपूर्ण तरीके से दबा कर रखा हैं.भारत ने हमेशा बड़े भाई की भूमिका के रूप में पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ दिया हैं, जबकि पाक कभी चीन कभी अमेरिका से मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र तैयार करने में कोई कसर नही छोड़ी.चौ दह साल के अंतराल के बाद भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों (डीजीएमओ) की बैठक 24 दितम्बर को सम्पन्न हुई। चौदह साल बाद ही सही लेकिन भारत औप पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की मुलाकात दोनों देशों के तल्ख रिश्तों में सुधार की नई पहल साबित हो सकती है। नियंत्रण रेखा पर आए दिन का संघर्ष अथवा सीमा संबंधी अन्य विवादों के निपटारे के लिए इस तरह की नियमित बैठकें होते रहना दोनों देशों के लिए जरूरी है।

How to cite this paper: Rajesh Gupta "Controversial Issues between India and Pakistan and their Solution" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-4, June 2022, pp.1250-1260, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd50298.pdf

IJTSRD50298

Copyright © 2022 by author(s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

तीन युध्दों से बरबादी

पिछले 66 वर्षों से दोनों देशों के बीच संबंध कभी मधुर नहीं रहे लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि पड़ोसी हैं तो क्यों न हंसी-खुशी से रहें, एक-दूसरे की प्रगति में भागीदार बनें, आपसी रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाए ताकि इसका फायदा जनता को भी मिल सके। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों की ओर से सरहद पर संघर्ष विराम, शांति और यथास्थिति कायम रखने की बात दोहरायी गई जिससे दोनों के आपसी रिश्तों को एक नए मुकाम तक पहुंचाया जा सके।यदि डीजीएमओ की बैठक सकारात्मक माहौल में होती रहे और यहां बनी सहमतियों को कार्यों में तब्दील किया जाए तो यह निश्चित रूप से भविष्य में दोनों के बीच तनाव कम करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है परन्तु अब तक के पाक के रवैये को देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा और नीतियों के मामले में किसी तरह की जल्दबाजी से पहले वेट एंड वाच की रणनीति अपनानी चाहिए।इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान को तीन युध्दों से बरबादी के अलावा कुछ और हासिल नहीं हुआ। इस वर्ष पाकिस्तान का सैन्य बजट 627 अरब रुपए का रहा जबकि भारत को अपने सैन्य बजट पर 2066 अरब रुपए खर्च

करने पड़े। सुरक्षा के नाम पर दोनों देशों का रक्षा बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। दोनों देश सम्पन्न राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आते। रक्षा बजट पर खर्च होने वाली राशि यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर खर्च हो तो दोनों देशों की तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी।इस वर्ष 30 सितम्बर को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच न्यूयार्क में डीजीएमओ की बैठक शुरू करने पर सहमति बनी थी। कारगिल युध्द के पूर्व इसकी अंतिम बैठक हुई थी। दोनों के बीच तल्खी की मुख्य वजह सरहद पर अशांति और एक प्रायोजित आतंकवाद है। रस्म अदायगी के लिए होने वाली प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों अथवा रक्षा मंत्रियों की बैठकों से न तो आज तक कोई नतीजा निकला है और न निकलने की उम्मीद ही है।

दोनों देशों के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं, उनमें हाथ मिलाने से अधिक जरूरी दिलों को मिलाना है। दिलों के मिलने से कई समस्याओं का निपटारा खुद ही हो जाता है। सैन्य अभियान महानिदेशकों की बैठक भी खानापूर्ति तक सिमट कर न रह जाए, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था करनी होगी।जनवरी 2013 में दो भारतीय जवानों की हत्या, जिसमें से एक जवान का सिर काटने की शर्मनाक घटना सामने आई थी, वहीं अगस्त में पाक की ओर से गोलीबारी में पांच भारतीय जवान शहीद हो गए थे। हाल ही में पाक सेना की ओर से करीब 15 दिनों तक सीमा पर गोलीबारी होती रही थी। 2013 में अब तक पाक की ओर से 195 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है और 267 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। नियंत्रण रेखा पर बेवजह होने वाला तनाव दोनों देशों के बीच दूसरे मुद्दों को प्रभावित करता है।

रिश्ते सुधारने की जरूरत

वर्ष 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का पाक सेना जब तब उल्लंघन करती रही है। भारत का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध रहे परन्तु उसके अकेले के चाहने से रिश्ते मधुर नहीं हो सकते। पाक की दोमुंही रणनीति के कारण वार्ताएं जब तब पटरी से उतरती रही हैं। आज भी सीमा पार आतंकियों को पनाह और प्रशिक्षण मिल रहे हैं। साथ ही पाक सेना उन प्रशिक्षित आतंकियों की घुसपैठ में मदद करती रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इसके जरिए उसका मकसद भारत में आतंकवाद को बढ़ाना और जम्मू-कश्मीर को अशांत करना है।

इस बैठक में ब्रिगेडियर स्तर पर जल्दी ही दो जगहों पर फ्लैट मीटिंग शुरू करने, अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर प्रयोग किए जाने वाले तंत्र को मजबूत करने, मौजूदा हॉटलाइन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ ही निर्दोष नागरिकों को सीमा पार करने पर जल्द लौटाने पर बनी रजाममंदी को निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। साथ ही पाक ने ऐसी व्यवस्था बनाने पर भी प्रतिबध्दता जताई है जिससे संघर्ष विराम समझौते को प्रभावी बनाया जा सके।

दोनों देशों के राजनेताओं को स्वीकारना होगा कि एक-दूसरे के खिलाफ नफरत का जहर फैला कर वे सत्ता की राजनीति करने में तो कामयाब हो सकते हैं लेकिन इससे रिश्तों में पड़ी गांठों के और उलझने का ही अंदेशा है। गांठों को सुलझाना है तो इसके लिए संबंध बेहतर होने के किसी भी अवसर का लाभ उठाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। संबंध बेहतर होने से दोनों देशों का सर्वांगीण विकास होने से कोई रोक नहीं सकता।हाल ही में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और पाक सेना को नए प्रमुख भी मिले हैं। दोनों ने भारत से रिश्ते सुधारने को प्राथमिकता देने की बात कही है। अब देखना होगा कि उनकी रजामंदी बातों में ही जाहिर होती है या जमीनी स्तर पर कुछ करके भी दिखाते हैं। इतिहास सबक लेने का सबसे अच्छा माध्यम है। जो हुआ, उसे भूलकर नई शुरुआत कभी न कभी तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर वह अभी आज से ही क्यों न शुरू हो जाए? दोनों देशों की तस्वीर और तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी।

परिचय

भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराने गहरे अविश्वास तथा तनाव का स्थान क्या उम्मीद ले पाएगी? क्या दोनों देशों की सरकारें अपने परंपरागत दृष्टिकोण से हटकर अमन की एक नई उम्मीद जगाने के प्रति वास्तव में गंभीर होंगी?दुनिया का सबसे ऊंचा और बहुत ही खर्चीला रणक्षेत्र सियाचिन क्या भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के हिमनद में बदलेगा? दोनों देशों के बीच दशकों पुराने गहरे अविश्वास तथा तनाव का स्थान क्या उम्मीद ले पाएगी? क्या दोनों देशों की सरकारें अपने परंपरागत दृष्टिकोण से हटकर अमन की एक नई उम्मीद जगाने के प्रति वास्तव में गंभीर होंगी?सियाचिन में सात अप्रैल की दुखद घटना के बाद आशा की एक किरण नजर तो आ रही है, क्योंकि इस घटना ने पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के माहौल को कुछ हद तक बदला है। ऐसा पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं और सैन्य प्रमुख के बयानों से लग रहा है। सियाचिन हिमनद (ग्लेशियर) भारत-पाकिस्तान के बीच विवादास्पद मुद्दों में से एक है। यह करीब 72 किलोमीटर लंबा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 21 हजार फीट है। यह काराकोरम रेंज के पांच सबसे बड़े हिमनदों में सबसे लंबा और कश्मीर में स्थित है। सात अप्रैल को सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान के 124 सैनिक और 11 नागरिक हिमस्खलन की चपेट में आने से 80 फीट गहरे बर्फ में दफ्न हो गए। काफी खर्चीले और लंबे बचाव व राहत कार्यों के बावजूद इन 124 सैनिकों और 11 नागरिकों का पता 50 दिन बाद कहीं जाकर लगा। तब भी सिर्फ तीन शव ही निकाले जा सके थे। वर्ष 1984 से भारत के 950 और पाकिस्तान के तीन हजार सैनिकों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। इनमें अधिकतर की मौत सियाचिन के भीषणतम और कठोर मौसम के कारण हुई है। यहां का तापमान शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। इसके बावजूद यह दोनों देशों की सेनाओं का स्थायी निगरानी केंद्र है। सालटोरो रिज में अपनी सेना को बनाए रखने के लिए माना जाता है कि भारत हर रोज पांच करोड़ रुपये खर्च करता है। यानी एक साल में 1, 825 करोड़ रुपये। लेखक, विश्लेषक आमिर मीर ने पाकिस्तानी अखबार द न्यूज में लिखा, "सियाचिन के मामले पर झगड़े ने 1984 से अप्रैल 2012 के बीच आठ हजार भारतीयों और पाकिस्तानियों की जानें लीं।" एक और पाकिस्तानी विशेषज्ञ और लेखक फारूख सलीम लिखते हैं कि "अगर इससे तुलना करें तो 1965 के भारत-पाक युद्ध में कुल हताहतों की संख्या 3, 800 थी।" सलीम पाकिस्तानी अखबार द न्यूज डेली में लिखते हैं, "आज तक के सभी शीत युद्धों में से सबसे बड़े शीत युद्ध का अभी तक के खर्चे का लेखा-जोखा अब पांच अरब डालर से भी अधिक है, जो कि पाकिस्तान के पूरे सालाना रक्षा बजट के बराबर है।" सियाचिन विवाद पर वह आगे

कहते हैं कि पाकिस्तान को यह दो सौ मिलियन डालर से तीन सौ मिलियन डालर सालाना के करीब पड़ता है, जो कि पाकिस्तानी मुद्रा में पांच करोड़ प्रतिदिन है। वह कहते हैं, "बिना किसी रणनीतिक, खनिज, सामरिक महत्त्व का यह विश्व का सबसे निरर्थक और मूर्खतापूर्ण युद्ध होना चाहिए।" [1]

भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 13 जून 2005 को सियाचिन आधार शिविर पर भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, "सियाचिन को सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, जहां रहना बहुत ही मुश्किल है। अब समय आ गया है कि हम प्रयास करें कि यह संघर्ष के केंद्र की जगह शांति के प्रतीक में बदले।" हालांकि 2005 के बाद से सियाचिन के मुद्दे पर स्थिति में कुछ हद तक बातचीत के अलावा कोई ठोस बदलाव होता नजर नहीं आया है। लेकिन सात अप्रैल, 2012 की उस भीषण घटना के बाद जो सबसे अहम बयान आया वह था पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी का माना जा सकता है। उन्होंने यह कहकर एक तरह से सभी को अचंभे में डाल दिया कि सियाचिन क्षेत्र का असैन्यीकरण होना चाहिए। जबकि यह वही कयानी हैं जिन्होंने सन् 2008 में कहा था कि वह अपने दृष्टिकोण में "भारत केंद्रित" हैं। कयानी ने कहा कि दो पड़ोसियों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, ताकि हर कोई जनता की भलाई पर ध्यान केंद्रित कर सके ...भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी शत्रुता को समझौते के जरिए हल किया जाना चाहिए। अठारह अप्रैल को कयानी ने कहा कि दोनों देशों को एक साथ बैठना चाहिए और सियाचिन सहित सभी मुद्दों को हल करना चाहिए। कयानी के इस बयान को इसलिए ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि यह बयान पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं बल्कि सेना के शीर्ष स्तर से आया है। यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान में सेना वहां के राजनीतिक प्रतिष्ठानों से ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तानी सेना देश की भारत और कश्मीर नीतियों को निर्देशित करती है और साथ ही यह फैसला करती है कि क्या पुनर्मेल को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं।भारत ने भी कयानी और पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों से आए बयानों का स्वागत किया। तीस अप्रैल को भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने लोकसभा में कहा कि सरकार सियाचिन हिमनद के असैन्यीकरण के लिए पाकिस्तान के साथ उद्देश्यपूर्ण वार्ता कर रही थी। जमीनी आधार तैयार करने के लिए दोनों देशों के रक्षा सचिव इस साल के अंत में इस्लामाबाद में मिलेंगे।siachin-and-soldiersअसल में सियाचिन की इस ताजा दुखद घटना ने पाकिस्तान की राजनीतिक सोच को काफी हद तक बदला है। यह एक ऐसा प्रस्थान बिंदु हो सकता है जहां से दोनों देश विवादों, खासकर सियाचिन के मुद्दे के हल के लिए गंभीरता के साथ ठोस कदम उठाने की सार्थक पहल कर सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि उसे सियाचिन से एकतरफा अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। 17 अप्रैल को स्कार्दू एयरपोर्ट पर शरीफ ने कहा कि इसे अहं का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान ने समाचार साप्ताहिक इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, "पाकिस्तान और भारत को सियाचिन से सैन्य बलों को एक साथ हटाना चाहिए।" पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय बहस के दौरान एक सदस्य ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि सियाचिन ग्लेशियर में 1984 से, जब से दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, अति कठोर मौसम के कारण जितने लोग मारे गए उतने आपसी संघर्ष में नहीं मारे गए। [2] इसी बहस के दौरान पाकिस्तान के ट्रेजेरी सीनेटर मोहम्मद अदील ने कहा, " हम करीब तीस साल से इतना महंगा युद्ध क्यों लड़ रहे हैं।" उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मानव गतिविधियां, जिसमें भारत और पाकिस्तानी बलों की ओर से फायरिंग भी शामिल है, इस इलाके में ग्लेशियर को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से कहा कि वह संसद को इस बारे में बताए कि वह ग्लेशियर को बचाने तथा सियाचिन विवाद का हल निकालने के लिए क्या कर रही है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने एक बयान जारी करके कहा, " दोनों देशों की सरकारें सियाचिन के मामले का समाधान करें, निश्चय ही विवादास्पद मुद्दों का भी... यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे संसाधनों को अपनी जनता के कल्याण और तरक्की के लिए खर्च करेंगे बजाय कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र पर बहुत ही खर्चीले बचाव एवं राहत अभियानों और अपनी सेनाओं की लागत पर।"इस घटना के बाद भारत से ज्यादा पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों के अंदर और आम जनता में सियाचिन के मुद्दे को लेकर बहस चल रही है। ऐसा भारतीय मीडिया में प्रकाशित समाचारों से लग रहा है। लेकिन असल पेच वहीं आकर फंसता है- वह है गहरे अविश्वास का माहौल। "खासकर भारत की ओर से पाकिस्तानी सेना को लेकर। सन् 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तानी सेना के सालटोरो रिज को हथियाने की योजना को लेकर ठोस सबूत दिए थे। सालटोरो रिज सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण-पश्चिमी भाग में पड़ती है। उस समय परवेज मुशर्रफ स्कार्दू ब्रिगेड कमांडर थे और इस आपरेशन के तत्कालीन आफिसर इंचार्ज भी। 13 अप्रैल, 1984 में भारतीय सेना ने हेलीबोर्न आपरेशन मेघदूत शुरू किया। कुमाऊं रेजीमेंट के पर्वतारोहियों को सालटोरो रिज पर, विशेष चोटियों को कब्जे में लेने के लिए, उतारा गया। 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानी फौज ने भी एक ऑपरेशन शुरू किया और बहुत ऊंचाई पर तथा बहुत ठंडी जलवायु में युद्ध लड़े गए किंतु जो पहले आए थे ऊंचाइयां उनकी ही रहीं। मात्र यह एक लाभ है जो भारतीय सेना थाल में परोस कर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है।"[3]

लेकिन असल मुद्दा यह है कि दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते कायम करने और विवादास्पद मुद्दों को हल करने का काम उन दोनों देशों की सेनाओं का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सरकारों का है। भारत में राजनीतिक सत्ता पर पाकिस्तान की तरह सेना का निर्देश नहीं चलता, इसलिए एक बड़ा देश होने के नाते भारत की सरकार को इस विवाद का हल निकालने के लिए सार्थक पहल करनी चाहिए। खासकर तब जब पाकिस्तान की सेना लचीला रुख अपना रही है। वैसे भी अविश्वास की खाई को सरकारें ही पाट सकती हैं। जो कि दोनों पड़ोसियों की जनता के हित में ही होगा। वैसे भी पाकिस्तान आज ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां कट्टरपंथी और आतंकवादी तत्त्व इस कदर हावी हैं कि उसे विखंडन की राह पर ले जा सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हाल ही में भारत की अपनी निजी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि जिस तरह भारत आतंकवाद का शिकार है उसी तरह पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। विश्लेषक भी अब यह मान रहे हैं कि कई मामलों में यह देखने में आया है कि पाकिस्तान के अंदर

जो आतंक का उद्योग है उस पर अब पाकिस्तानी सेना और सत्ता प्रतिष्ठान का उस तरह से नियंत्रण नहीं है जैसा कि पहले रहता था।एक टूटता और क्रमश: कमजोर होता पाकिस्तान भारत के हित में नहीं होगा। क्योंकि भविष्य में पाकिस्तान में सक्रिय विघटनकारी तत्त्व अपनी ताकत का अधिक से अधिक इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेंगे।हालांकि इस अविश्वास को पाटना कोई आसान काम भी नहीं है। खासकर भारत सरकार के लिए, क्योंकि भारत में राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठानों में एक तबका ऐसा है जो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के सामान्य संबंध बनाने के खिलाफ लगातार मुखर रहता है। खासकर भारत में राजनीति का दक्षिणपंथी खेमा, जिसे पाकिस्तान विरोध के नाम पर समय-समय पर राजनीतिक खुराक मिलती रहती है। अगर इसे पार पाने में कुछ हद तक कामयाबी मिल भी जाए तो हथियारों की लॉबी का पूरा एक ऐसा जाल है जो दोनों देशों के बीच किसी तरह से संबंध सामान्य नहीं होने देना चाहता। अंतरराष्ट्रीय हथियार गिरोह का यह "छिपा" हुआ हाथ सेना से लेकर राजनीति के गलियारों और मीडिया तक हर जगह मौजूद रहता है और देश भक्ति और राष्ट्रवाद की आड़ में अपना खेल दिखलाता रहता है। भारत-पाकिस्तान के बीच दोस्ती इस अंतरराष्ट्रीय हथियार लॉबी के हित में नहीं है। शत्रुता ही उसका असली मुनाफा है, क्योंकि इसके कारण ही वह अपना खजाना भरता है। शत्रुता कायम रहेगी तो हथियार भी बिकेंगे। सन् 2010 में ही भारत ने 333 करोड़ अमेरिकी डालर के हथियार खरीदे। हथियार आयात करने के मामले में भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश है और कई विकसित देशों से हथियार मंगाता है। हथियारों की खरीद, उनके आधुनिकीकरण जैसे कि राकेट, मिसाइल और सामरिक महत्त्व के उपग्रहों की लांचिंग पर भारत का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, जबकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य, साफ पेयजल और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यही हाल लगभग पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के वक्तव्य के बाद भारतीय मीडिया के एक हिस्से में अचानक पाकिस्तान के प्रति आक्रामकता दिखलाई देने लगी है। सुरक्षा, सावधानी और विश्वासघात की कहानियां बढ़-बढ़ कर सुनाई जाने लगी हैं।हथियार लॉबी का दखल किस तरह से है इसका हवाला अंग्रेजी समाचार पत्र डेक्कन हेराल्ड ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में दिया है। हेराल्ड ने एक अप्रैल के अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा है, "जैसे-जैसे भारत सैन्य उपकरणों पर बहुत अधिक खर्च करने वाले देशों में से एक देश के रूप में उभरकर सामने आ रहा है, वैसे-वैसे लग रहा है कि अफसरों के एक हिस्से, जिसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, ने सिद्धांतों और विश्वास पर रिटायरमेंट के बाद चलने का निर्णय ले लिया है। वैश्विक सैन्य उद्योग के परिसरों के प्रलोभन में आकर उन्होंने स्वयं ही इस चकाचौंध कर देने वाली कारपोरेट दुनिया के गंदे हिस्सों में, करोड़ों के हथियारों के ठेकेदारों के लॉबिस्ट के रूप में प्रवेश ले लिया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विषय में सैन्य बल में से कोई बात करना पसंद नहीं करता। इनमें से बहुत से हथियार के ठेकों में लॉबिस्ट या बिचौलियों के अस्तित्व से इनकार करते हैं, किंतु निजी तौर पर वे मानते हैं कि यह व्यापार पनप रहा है। इन लॉबिस्टों के लिए पुराने लोगों का नेटवर्क बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि उनमें से अधिकतर बाहर की दुनिया के लिए अनाम और गुमनाम रहते हैं। अगर कुछ मामलों में भ्रष्टाचार की गंध भी उठे जिसके कारण कुछ फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने या कांट्रेक्ट रद्द करने की स्थिति आ भी जाए तो भी लॉबिस्ट कानून के परिदृश्य से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि कागजों पर उनके नाम नहीं होते।"पिछले दिनों सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह ने एक घटिया स्तर की खरीद के लिए उन्हें घूस की पेशकश की थी। जनरल वी.के. सिंह के इस बयान ने एक तरह से विवादों का भानुमति का पिटारा खोल दिया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.पी. मलिक ने डेक्कन हेराल्ड के साथ बातचीत में माना कि " हथियारों का व्यापार, पूरे विश्व में, बहुत ही प्रतिस्पर्धी है और साथ ही अनैतिक भी। आपके पास दलाल, डीलर, भ्रष्ट अधिकारी और नेता होते हैं। यहां तक अपने देश के उत्पादनकर्ताओं के लिए नेता लॉबिंग करने वाले बन जाते हैं। उत्पादनकर्ता और डीलर अक्सर उन लोगों को घूस और कमीशन देने की कोशिश करते हैं जिन्हें वे आसानी से अपनी पकड़ में आने वाला समझते हैं।""वायुसेना के एक अधिकारी 1980 के दशक की एक घटना याद करते हुए कहते हैं कि जब भारतीय वायुसेना के पास एक खास तरह के वॉल्व की अत्यधिक कमी थी, उस समय उसकी कीमत 40 रुपए प्रति वॉल्व थी। यह सोवियत गणतंत्र से आता था। एक दिन एक भद्र पुरुष वायु भवन में आए और उन्होंने हूबहू वॉल्व की बिक्री का प्रस्ताव रखा, जिसकी कीमत पांच हजार रुपए प्रति वॉल्व बताई। उनके पास उनके सिंगापुर स्थित गोदाम में स्टाक तैयार था जैसा कि यह अखबार अपनी इस रिपोर्ट में आगे लिखता है कि वह एक शुरुआत थी। इसके बाद बाढ़ आ गई। पहले जगुआर फाइटर्स और फिर बोफोर्स तोप और साथ ही आर्थिक उदारीकरण।लेकिन इस तरह की बाधाएं तो हमेशा बनी ही रहेंगी। भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य और आगे की दिशा में ले जाने के लिए जरूरत है एक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की। इससे कुछ बात बन सकती है। कम से कम सियाचिन के मामले में तो कुछ हो ही सकता है। जहां दो ऐसे देश जिनकी अधिसंख्य जनता को ठीक से रोटी नहीं मिलती, और जो आधि सदी पहले एक थे, निरर्थक रूप से अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं।[4]

आज अतिआधुनिक तकनीक के दौर में सियाचिन में बिना किसी सेना की मौजूदगी के एक-दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। भारत के पास तो रीसेट-1 जैसा अतिआधुनिक स्वेदशी रडार इमेजिंग सेटेलाइट है, जो उसने हाल ही में लांच किया है। इस सेटेलाइट को लांच करके भारत ने अंतरिक्ष और सुरक्षा क्षमताओं में एक बहुत लंबी छलांग लगाई है। यह रडार दूसरे देश के सैन्य अभियानों को देख सकता है। इसके जरिए बादलों से ढके क्षेत्र में भी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।इसलिए भारतीय नेतृत्व को सिर्फ कर्णप्रिय बातें ही नहीं करनी होंगी बल्कि बातचीत और विवादास्पद मुद्दों के समाधान के लिए जमीनी स्तर पर ठोस पहल भी करनी होगी। साथ ही पाकिस्तानी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व सियाचिन की घटना के बाद जिस तरह के सकारात्मक संदेश दे रहा है उसे हकीकत में बदलने के लिए उसे कुछ सकारात्मक करता हुआ नजर भी आना पड़ेगा। निश्चय ही बड़ा देश होने के नाते भारत की जिम्मेदारी भी बड़ी है। दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जो पहल एक बार फिर शुरू हुई है उसे सतत गति देनी होगी। जैसे की दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए सीमा पर एक एकीकृत चौकी खोली जा रही है। दोनों सरकारों ने निश्चय किया

है कि वे भारत-पाकिस्तान वाणिज्य परिषद का गठन करेंगे। इसके अलावा अहम बात यह है कि पाकिस्तान भारत को अति वरियता वाले राष्ट्र का दर्जा देने के प्रयास के बहुत करीब है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री मखदूम अमीन फहीन ने पिछले दिनों भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहा था, "हमें यह समझना चाहिए की लडने में कोई फायदा नहीं है। हम क्यों नहीं संवाद करते? क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? हम व्यापार के जरिए बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी बचे हुए मुद्दे भी तब सुलझा लिए जा सकते हैं।"दोनों देश चार बड़े यु़द्धों की विभिशसा को देख चुके हैं, सीमा पार दोनों ओर की जनता अमन चैन से अपने अपने वतन का विकास चाहती हैं, वही पाकिस्तान हर वक्त नये जुगाड़ में लगा रहता हैं, कैसे भारत की टांग अड़ाई जाएं.[5]

भारत - पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा

24 अक्टूबर 1947 को कबालियों के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण के बाद से ही कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने का फैसला किया जिसके बाद भारत और पकिस्तान के बीच आमने - सामने से युद्ध शुरू हो गया। भारत इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र गया जहां संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करते हुए युद्ध विराम का ऐलान किया लेकिन पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर भूभाग पर भारत को नियंत्रण नहीं मिल सका। इस युद्ध के बाद से ही एक ओर जहां भारत पाकिस्तान अधिकृत को अपना अभिन्न अंग बताते हुए वापस लौटाने की बात कहता है तो वहीं पाकिस्तान की मंशा ये है कि वो बाकी के कश्मीर पर भी अपना कब्ज़ा कर ले ।कश्मीर में चरमपंथी उभार - कश्मीर घाटी में चरमपंथी उभार 1989 से दिख रहा है। कुछ इस्लामिक चरमपंथी गुटों ने कश्मीर को भारत से आज़ाद करने और पाकिस्तान में शमिल किए जाने के लिए विरोध शुरू किया। उस दौर से शुरू ये विद्रोह आज भी रह - रह कर घाटी में देखने को मिलता रहता है। हालाँकि ये पूरी दुनिया को मालूम है कि कश्मीर में आज़ादी की मांग करने वाले इन इस्लामिक चरमपंथी गुटों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है जो उन्हें पैसे और हथियार दोनों मुहैया कराता रहा है।

बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कश्मीर मु़द्दे पर एक एक विवादास्पद बयान दिया है। राष्ट्रपति ट्रम्प के मुताबिक़ अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने इस बयान के पीछे तर्क देते हुए कहा है कि जापान के ओसाका में हुई G - 20 शिखर बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मामले को सुलझाने में उनकी मदद मांगी थी। हालाँकि ट्रम्प के इस बयान का भारत ने तुरंत खंडन किया है। इस मामले पर संसद में बयान देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि - मैं सदन को स्पष्ट रूप से आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला समझौता और लाहौर घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करने का आधार प्रदान करता है। ग़ौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बातें अमेरिका गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इ दौरे के दौरान कही है। बीते दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान अमेरिका दौरे पर थे। तीन दिन के अमेरिका दौर से लौटे इमरान ख़ान अपनी इस यात्रा को बेहद सफल मान रहे हैं। हाँलाकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की अमेरिका ने कोई मदद नहीं की है। पाकिस्तान के इस दौरे के दौरान अमेरिका का पूरा ध्यान अफ़ग़ानिस्तान में शांति वार्ता को लेकर केंद्रित रहा। अमेरिकी अधिकारियों के मु़ताबिक़ पाकिस्तान पहले अफ़ग़ानिस्तान में शांति बहाली को लेकर ज़रूरी कदम उठाए फिर कही जा कर पाकिस्तान के साथ व्यापारिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम किया जा सकेगा।18 सितम्बर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारत के 18 जवान शहीद हो गए। सैन्य बलों की कार्रवाई में सभी चार आतंकी मारे गए। यह भारतीय सेना पर किया गया, लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले को बहुत गम्भीरता से लिया। पहले हुए कई हमलों (पठानकोट आदि) की तरह इस हमले में भी आतंकवादियों के पाकिस्तान से सम्बन्ध होने के प्रमाण मिले, जिसके कारण भारतभर में पाकिस्तान के प्रति रोष प्रकट हुआ और भारत सरकार ने कई अप्रत्याशित कदम उठाए जिनसे भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध प्रभावित हुए।[6]

- भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर विश्वभर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम छेड़ दी।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत की विदेश मन्त्री ने आतंक का पोषण करने वाले देशों की निन्दा की। पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कहा कि कश्मीर छीनने का सपना पूरा नहीं होगा।
- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के बयान 'खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते' के साथ ही भारत ने सिन्धु जल सन्धि की समीक्षा शुरु कर दी। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्यवाही बताया[1], और भारत के विरुद्ध परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी दी। सन्धि रद्द होने के डर से पाकिस्तान ने विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाया।
- भारत ने नवम्बर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले दक्षेस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने की घोषणा की। बांग्लादेश, अफगानिस्तान व भूटान ने भी भारत का समर्थन करते हुए बहिष्कार की घोषणा की।
- भारत ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर पुनर्विचार की घोषणा की।
- 29 सितम्बर 2016 को भारत के डीजीएमओ ने प्रेस कॉंफ्रेंस में बताया कि भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए।

विचार-विमर्श

भारत पाकिस्तान सीमा विवाद

भारत और पकिस्तान की सीमाएं कुल 4 राज्यों से होकर गुज़रतीं हैं जिनमें पंजाब, गुजरात, और राजस्थान के साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित सर क्रीक सीमा रेखा को लेकर विवाद रहा है। सर क्रीक सीमा रेखा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत अहम् हिस्सा है बल्कि ये गुजरात राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।ग़ौरतलब है कि सर क्रीक सीमा रेखा विवाद

कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्टता के कारण है। आज़ादी से पहले, ये क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसीडेंसी का भाग था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का ही हिस्सा रहा। ये क्षेत्र सामरिक लिहाज़ से बेहद महत्त्व है। ये क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से भी एक है जिसके कारण ये मछुआरों के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। साथ ही इस क्षेत्र के समुद्र के नीचे तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद होने के कारण भी इस क्षेत्र का अपना अलग महत्त्व है।[7]

भारत पाकिस्तान जल विवाद

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से तंग आकर भारत ने बीते दिनों सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत के हिस्से में आने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं देने की बात कही है। सिंधु नदी जल समझौते के मुताबिक़ भारत में पश्चिमी नदियों (झेलम, चिनाब, सिंधु) के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत इनका क़रीब 20 प्रतिशत अपने इस्तेमाल में ले सकता है। सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों से 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर करने का अधिकार है। पश्चिमी नदियों के पानी से भारत 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई कर सकता है। इसके अलावा भारत इन नदियों पर जलविद्युत परियोजनाएँ भी बना सकता है, हालाँकि भारत उस को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल करना होगा।जानकारों का कहना है कि भारत का ये फैसला उन छोटी-बड़ी पहलों का एक हिस्सा है, जो भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठा रहा है। विशेषज्ञ इसे पानी की सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। ग़ौरतलब है कि इन तीनों नदियों पर डैम बनाने के बाद पानी पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिये इस्तेमाल किया जाएगा।पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्ध अपने निम्नतम स्तर पर रहे. ख़ास कर इमरान की भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में पब्लिक रेलियों में बदजुबानी और अपमानसूचक शब्दों के प्रयोग भी देखे गये.२०१८ से २०२२ इन चार वर्षों में भले ही बॉर्डर पर सीज फायर की स्थिति लम्बे समय तक बरकरार रही, मगर रिश्तों में कडवाहट ही रही. दोनों देशों के हेड ऑफ़ स्टेट के मध्य फोन कॉल संवाद भी समाप्त हो गये थे. बाईडन कॉल करता नहीं मोदी फोन उठाते नहीं यह उक्ति इमरान को घेरने के लिए हमेशा विपक्षी दल खान को घेरते थे.पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद खान ने भारत विरोधी राग को हर जगह अलापा. हालांकि संसद में अविश्वास मत पास होने के बाद जब इमरान अपदस्थ हुए तो उन्होंने एक के बाद एक हर पब्लिक रेली में भारत और भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफे की थी.अंतिम वायसराय लोर्ड माउंट बेटन की विभाजन योजना के अनुसार सभी रजवाड़ों तथा रियासतों को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया, कि वे चाहे तो भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के अथवा वे स्वतंत्र रूप से अलग भी रह सकते है. इस तरह हैदराबाद व जूनागढ़ की तरह जम्मू कश्मीर ने भी स्वयं को किसी भी देश में न मिलाकर स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था.पाकिस्तान द्वारा बार बार प्रलोभन के मौके मिलने के उपरांत भी जम्मू कश्मीर के राजा हरिसिंह ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके उकसावे की निति के तौर पर पाकिस्तानी ने अक्टूबर 1948 में हरिसिंह के सम्पूर्ण राज्य पर काबाइली हमला कर दिया.[8]

हरिसिंह भारत के पास सैन्य सहायता के लिए आए, उस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय के सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये, तदोपरान्त भारतीय सेना ने मौर्चा संभाला तथा 24 घंटों में युद्ध को पूर्व स्थति में ला दिया. पाकिस्तानी घुसपैठियों जान बचाकर भाग गये, सेना पीछा करती हुई लाहौर तक चली गईं, युद्ध विराम की घोषणा के बाद सेनाएं वापिस बुला ली गईं.इसी समय भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु एक बड़ी चूक कर जाते हैं, जिनका खामियाजा आज तक भारत के लोग भुगत रहे हैं. इस विषय के हल के लिए वे संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर विवाद को किसी हल के लिए ले जाते हैं. मगर आज भी कश्मीर विवाद यू का यू पड़ा हैं, जिस पर किसी तरह का समाधान नही निकल पाया हैं.

भारत - पाकिस्तान सम्बन्ध

ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से 'द्विराष्ट्र सिद्धांत' पर अलग हुआ था। भारत पाकिसान के साथ भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और जातीय सम्बन्ध साझा करता है लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते आपसी मतभेद, शत्रुता और संदेह के कारण पिछले 72 सालों से बेहतर नहीं हो पाए हैं। आज़ादी के बाद से अब तक भारत - पाकिस्तान के बीच चार युद्ध हो चुके हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र जैसे कदम उठाए गए हैं लेकिन शुरू से ही नापाक हरकते करने वाले पाकिस्तान के लिए अब इसके कोई मायने नहीं रह गए हैं।

इंस्ट्रमेंट ऑफ़ एक्सेशन

26 अक्टूबर 1947 को जम्मू - कश्मीर का विलय भारत में हो गया था। भारत में कश्मीर के विलय को लेकर महाराजा हरी सिंह ने 'इंस्ट्रमेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान इस बात पर भी सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। बाद में मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने जिसके बाद भारत, जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया। जम्मू - कश्मीर को लेकर संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दिया गया।

नेहरू - लियाक़त समझौता 1950

प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाक़त अली खान के बीच 8 अप्रैल 1950 दिल्ली में एक समझौता हुआ था। इस समझौते का मक़सद दोनों देशों के बीच शरणार्थी, संपत्ति, अल्पसंख्यकों के अधिकार और भविष्य में युद्ध की संभावनाए न हो जैसे मुद्दों पर समझौता था।[9]

सिंधु - नदी जल संधि 1960

आज़ादी मिलने के बाद कई अन्य मुद्दों की तरह भारत - पाकिस्तान के बीच पानी के मुद्दे को लेकर भी विवाद शुरू हो गया था। भारत से पकिस्तान जाने वाले इन छः नदियां - झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को लेकर विवाद चल रहा था। सालों चली बातचीत के बाद 19 सितंबर, 1960 को विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु - नदी जल संधि समझौता हुआ।समझौते के मुताबिक़ 3 पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलज) के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। जबकि बाकी 3 पश्चिमी नदियों (झेलम, चिनाब, सिंधु) के पानी के

पाकिस्तान को देना तय हुआ था। ग़ौरतलब है कि सिंधु - नदी जल समझौता 12 जनवरी 1961 से लागू हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब ख़ान ने रावलिपिंडी में दस्तख़त किये थे। इसके अलावा इन दानियों का एक बहुत छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला हुआ है। सिंधु - नदी जल संधि पर पाकिस्तान की आपत्ति ये है कि भारत, पाकिस्तान के हिस्से के पानी का प्रयोग कर रहा है। जबकि भारत का कहना है कि ग्लेशियर और बरसात के कम होने के कारण सिंधु नदी में पानी कम हो रहा है , इसके अलावा पाकिस्तान इस मुद्दे को ढ़ाल बना कर सीमापार आतंकवाद से ध्यान भटकाना चाहता है।

ताशकंद समझौता 1966

ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। ये समझौता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। ताशकंद समझौते के अनुसार ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने विवादों का शान्तिपूर्ण तरीके से निपटारा करेंगे। ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था।

शिमला समझौता 1972

1971 में हुए भारत - पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था। ये समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। दरअसल 1971 के भारत - पाकिस्तान युद्ध के दौरान क़रीब 90 हज़ार सैनिकों को भारत ने बंदी बनाया था और पाकिस्तान के लम्बे भूभाग पर भारत ने कब्ज़ा भी कर लिया था। इस सब के परिणामस्वरूप तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था।

शिमला समझौता के मुख्य बातें:

- शिमला समझौते के मुताबिक़ दोनों देशों के सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप चलेंगे।
- दोनों देशों के बीच होने वाले सभी मतभेदों और आपसी विवाद को द्विपक्षीय बातचीत के ज़रिए हल किया जायेगा।
- यदि दोनों देशों के बीच कोई मुद्दा लबित रह जाता है तो कोई देश उस मुद्दे को लेकर स्थिति में बदलाव करने की एकतरफा कोशिश नहीं करेगा।
- दोनों देश किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जो शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरा हो।
- समानता और आपसी लाभ के आधार पर शांति पूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे।
- एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता व सम्प्रभुता का सम्मान करेंगे
- समानता और आपसी लाभ के आधार पर एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे
- 25 सालों से दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करने वाले कारकों को शांति पूर्ण ढंग से हल किया जायेगा
- शिमला समझौते के तहत संचार, सीमाएं खोलने, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने दोनों देशों के नागरिकों की यात्रा सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही गई
- आर्थिक और दूसरे सहमति वाले क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना का भी ज़िक्र किया गया
- विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना
- भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस बुलाने का ऐलान
- युद्धबंदी के भारत भी नियंत्रण रेखा का सम्मान करना और नियंत्रण रेखा को बदलने की एकतरफा कोशिश न करने जैसे फैसले शिमला समझौते के तहत हुए थे।[8]

हालाँकि युद्धबंदियों को भारत द्वारा वापस लौटाने और अपनी ज़मीन को वापस पाने के बाद पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया।

नॉन-न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1988

ये समझौता भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच 21 दिसंबर, 1988 को समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों में कटौती और किसी दूसरे देश के ज़रिए परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का वचन दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर पर संसद का प्रस्ताव 1994

22 फरवरी,1994 को संसद के दोनों सदनों ने पारित एक प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया। प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। भारत अपने इस भाग को ख़ुद में विलय कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसके अलावा इस प्रस्ताव में इस बात का भी ज़िक्र किया गया कि भारत में पर्याप्त क्षमता और संकल्प है कि वो पाकिस्तान के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दे जो देश की एकता, क्षेत्रीय अंखडता और सुरक्षा के ख़िलाफ़ हो। 1994 में पारित इस प्रस्ताव में भारत ने पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के उन इलाकों को खाली करने की बात कही जिस पर उसने कब्जा किया है।सदन का मानना था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को हथियार और धन की सप्लाई के साथ-साथ आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद दी जा रही है।

लाहौर घोषणा पत्र 1999

शिमला समझौते के बाद भारत ने एक बार फिर लाहौर घोषणा पत्र के ज़रिए दोनों देशों को बेहतर बनाने के प्रयास किया। 21 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के बीच लाहौर में एक घोषणा पत्र पर दस्तख़त हुआ। लाहौर घोषणा पत्र में पहले के सभी मुद्दों को भूलकर दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की पेशकश भारत की ओर से की गई। इसके अलावा नई दिल्ली से लाहौर तक हफ़्ते में दो बार बस सेवा सदा -ए - सरहद की शुरुआत की।[7]

लाहौर घोषणा पत्र 1999 के मुख्य बातें:

- नियमित अंतराल पर दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठक करेंगे और आपसी हितों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे

- विश्व - व्यापार से जुड़े मुद्दों पर विचार - विमर्श की सहमति
- वीज़ा नियमों को आसान बनाना, युद्धबंदियों या असैनिक बंदियों की जाँच के लिए मंत्रीस्तर पर दो सदस्यीय समिति का गठन
- सुरक्षा धारणाओं और परमाणु सिद्धांतों पर विचार विमर्श करेंगे
- मिसाइल उड्डयन परीक्षणों की पूर्व सूचना देना
- परमाणु ख़तरों को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क़दम उठाएँग
- पहले न्यूक्लियर टेस्ट न करने के वादे का पालन करेंगे
- UN चार्टर के सिद्धांतों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता निभाएंगे
- आपसी विश्वास के लिए समय समय पर विचार - विमर्श
- सुरक्षा, नि:शस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता
- लाहौर घोषणा पत्र को एक दूसरे की संसद में मज़ूर किया गया

इस घोषणा के तीन बाद ही पकिस्तान ने कारगिल युद्ध छेद दिया।

परिणाम

भारत पाकिस्तान के आर्थिक सम्बन्ध

भारत - पाकिस्तान ट्रेड आर्गेनाईजेशन के मुताबिक़ 2018 - 19 में भारत पाकिस्तान के बीच कुल 2.05 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापर था। मौजूदा समय में भारत पकिस्तान को सब्जियाँ, कपास, प्लास्टिक और लोहा व इस्पात जैसे सामानों का निर्यात करता है जबकि भारत पकिस्तान से मसाले, फल, और सीमेंट जैस सामानों को खरीदता है।

भारत ने पाकिस्तान से वापस लिया MFN दर्ज़ा

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते भारत ने इस साल पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन के भी दर्ज़ा वापस ले लिया। ग़ौरतलब है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा किसी देश के साथ द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा दिए जाने के लिए दिया जाता है। MFN दर्जे के ज़रिये ही किन्हीं भी 2 देशों के बीच में साझा व्यापार की नींव तैयार होती है। MFN दर्जे के ज़रिए इसमें आयातित सामानों पर लगने वाले सीमा शुल्कों तथा अन्य दूसरे टैक्सों में सहूलियत दी जाती है। इसके अलावा MFN घरेलू प्रशासन के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को और आसान बनाया जाता है साथ ही उनमें और अधिक पारदर्शिता लाई जाती है।

आतंकवाद के चलते FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ पाकिस्तान

आतंकवाद को पनाह देने के चलते अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की सूची में रखा है। FATF के मुताबिक़ पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने में नाकाम रहा है। FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अक्तूबर, 2019 तक पाकिस्तान उसकी 27 मांगों पर काम नहीं करता है तो उसे 'ग्रे' से 'ब्लैक' लिस्ट में डाल दिया जाएगा।[6]

परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों में चीन कर रहा है पाकिस्तान की मदद

भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान, दोनों के ही पास परमाणु संपन्न हथियार हैं लेकिन उनके परमाणु सिद्धांत परस्पर विरोधी हैं। भारत एक ओर जहां 'परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करना'की नीति का पालन करता है, तो वहीं पाकिस्तान की ऐसी कोई मंशा ज़ाहिर नहीं होती है। इसके अलावा मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों में चीन और पाकिस्तान की मदद कर रहा है।

पाकिस्तान की वजह से ठप है सार्क संगठन

कई प्रमुख क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में मुश्किलें पैदा करके पाकिस्तान ने सार्क को निष्क्रिय बना दिया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण, भारत समेत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे देश सार्क शिखर सम्मेलन से पीछे हट गए है। सार्क शिखर सम्मेलनों का न होना भी भारत - पाकिस्तान के बीच की खाई को और बढ़ा रहा है।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कैसे लगे लगाम ?

दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। जानकारों का कहना है कि सीमा सुरक्षा को और मज़बूत और आधुनिक बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा समयबद्ध तरीके से व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली को भी तैयार किया जाना ज़रूरी है। साथ ही भारतीय तट रक्षक और दूसरी एजेंसियों के बीच उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित करके तटीय सुरक्षा और चौकसी को मजबूत किया जाना चाहिए जिनमें भारतीय नौसेना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, कस्टम और बंदरगाह शामिल हैं।पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से POK पर कब्जा कर रखा हैं, वही वो कश्मीर घाटी में आए दिन घुसपैठ व आतंकवादी भेजकर इंडो पाक रिलेशन को उसी स्थति में रहने देना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान की सेना का राजनीति पर वर्चस्व कायम रहे.अप्रैल 1965 में पाक की ओर से घुसपैठिये भेजकर कच्छ के रन तथा कश्मीर में घुसपैठ की शरारत की गईं, लाल बहादुर शास्त्री के कुशल नेतृत्व में पाक की इस हरकत को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए सैन्य सैन्य कार्यवाही शुरू की गईं, जो 1965 के भारत पाक युद्ध में बदल गईं.4 महीने तक दोनों देशों के बिच जंग चलती रही, 22 अक्टूबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ की दखल से यह युद्ध समाप्त हुआ, मगर इससे पूर्व ही पाकिस्तान के सैनिक हथियार डालकर भाग चुके थे.तक़रीबन 7-8 माह बाद सोवियत संघ रूस उस समय भारत का परम मित्र था, उसके कहने पर भारत पाक समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में सम्पन्न हुआ, लेकिन इस दौरान ताशकंद गये भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गईं थी.

इस समझौते के उपरान्त कुछ साल शान्ति पूर्ण तरीके से गुजर ही रहे थे, कि पूर्वी पाकिस्तान में याहया खान के अत्याचारों के कारण गृहयुद्ध शुरू हो गया. वहां के बंगाली भारत में आकर शरण लेने लगे.नई दिल्ली में आने वाले बंगलादेशी शरणार्थीयों की संख्या 1 करोड़ तक पहुच गईं, भारत ने उनके खाने पीने

तथा अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की तथा उन्हें मेहमान स्वरूप रखा.जो पाकिस्तान को नागवार गुजरा, उसने 2 दिसम्बर 1971 को वायुसेना से भारतीय एयरबेस पर हमला शुरू कर दिया. भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब दिया, इस जवाबी कार्यवाही में कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए, तथा एक नये राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में जन्म हुआ.1971 के इंडिया पाक वॉर के बाद 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता किया गया. इस समझौते में भारत ने पाकिस्तान को के साथ युद्ध के मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए सरेंडर कर चुके 90,000 सैनिकों सहित विजित क्षेत्र को पाकिस्तान को लौटा दिया. यह वजह हैं कि आज भी इसे भारत की सबसे बड़ी कुटनीतिक हार माना जाता हैं.वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध तथा 1972 के शिमला समझौते के बाद दोनों देशों के बिच सामाजिक, धार्मिक, राजनितिक व आर्थिक सम्बन्धों में सुधार हो रहा था, कि 1979 को सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, भारत सोवियत संघ के साथ था,जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का समर्थक था. इसके चलते दोनों देशों के संबंध एक बार भी कटुताभरे रहे.1985 में भारत की ओर से एक बार फिर मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की पहल की, मगर भारत का यह प्रयास नाकाम रहा. कुछ वर्ष बाद 1998 में भारत ने पोकरण में अमेरिका की आँखों में धूल झोकते हुए अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था.जिससे एक बार फिर दोनों में कटुता पूर्ण संबंध स्थापित हो गये. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत पाक के सबंधों में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किये,जिनमें 1999 में ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा का शुभारम्भ किया.पाकिस्तान हमेशा अपनी पालिसी के अनुसार कार्य करता रहा, भारत के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में फिर से घुसपैठ शुरू कर दी. जिसका नतीजा भारत पाकिस्तान के मध्य एक और युद्ध जिसे कारगिल युद्ध कहा जाता हैं, के रूप में सामने आया. इस युद्ध में भी पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी. मगर इससे संबंध फिर से खराब होने लगे.दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार के लिए 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशरफ के मध्य आगरा सम्मेलन हुआ. इस सम्मेलन में भी पाकिस्तान के प्रतिनिधि की कश्मीर हठ के कारण बातचीत आगे नही बढ़ पाई, तथा यह समझौता भी बेनतीजा ही रहा.एक बार फिर दोनों देशों के सम्बन्धों में दरार जब आई तब 2001 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारतीय संसद भवन पर आतंकवादी हमला किया. वर्ष 2003 तक दोनों देशों के रिश्तों में कटुता रही.एक बार फिर 20 जनवरी 2006 को लाहौर और अमृतसर के मध्य बस सेवा शुरू होने से दोनों देशों की जनता की शान्ति की नई उम्मीद जगी. मगर 26 नवम्बर 2008 को पाकिस्तान द्वारा मुंबई की ताज होटल पर किये जाने से पूरे विश्व को यह पता चल गया, कि पाकिस्तान के साथ मित्रता सांप को दूध पिलाने जैसा हैं.इस्लामाबाद में सरकार में बदलाव न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में शिष्टाचार बहाल करने के लिए एक अग्रदूत बन सकता है, बल्कि दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए भी प्रोत्साहन दे सकता है। इमरान खान के विपरीत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न तो एक लोकतंत्रवादी हैं और न ही एक अहंकारवादी, जो एक वैकल्पिक वास्तविकता में रहते हैं। इसके विपरीत, शहबाज शरीफ एक अनुभवी राजनेता हैं, जो भारत के साथ संबंधों में सुधार की अनिवार्यता को समझते हैं। सौभाग्य से, उन्हें भारत के प्रति किसी पहल या पहुंच में पाकिस्तानी सेना का समर्थन भी प्राप्त होगा। अपने तौर पर, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत में सतर्क रहते हुए उसके द्वारा की गई किसी भी पहल पर प्रतिक्रिया देने के खिलाफ नहीं हो सकता। [5]

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की प्रतिक्रिया सामान्य से अधिक कुछ भी नहीं थी। दो सरकारों के प्रमुखों के लिए शिष्टाचार का आदान-प्रदान करना सामान्य है। यहां तक कि यह उस विषाक्तता से कुछ बदलाव से कुछ बदलाव को परिभाषित करता है, जो इमरान खान के शासन के दौरान दोनों देशों के संबंधों में पैदा हो गई थी। आगे चलकर यह उम्मीद की जा सकती है कि कूटनीतिक मर्यादा और शालीनता, जिसे गाली देने वाले इमरान खान ने हवा में उड़ा दिया था, एक बार फिर आदर्श बन जाएगी। यह अपने आप में द्विपक्षीय संबंधों में तनाव और कड़वाहट को कम करने में मदद करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 2 दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच किसी प्रकार के जुड़ाव की संभावना का द्वार खोलेगा। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि केवल शैली में परिवर्तन ही कुछ सबसे गंभीर मुद्दों, जैसे कि क्षेत्रीय विवाद, कश्मीर मुद्दा और निश्चित रूप से आतंकवाद, जो भारत-पाकिस्तान संबंधों को बाधित करता है, का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन समय आ गया है कि दोनों देशों और कुछ मायनों में भारत से अधिक पाकिस्तान, बकाया मुद्दों और अस्तित्व के मुद्दों के बीच अंतर करें, जो उस राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। अधिकांश देश ऐसे मुद्दों को बातचीत के माध्यम से प्रबंधित करते हैं, युद्ध या छद्म युद्ध नहीं छेड़ते। शायद समय आ गया है कि पाकिस्तान भी अन्य देशों के अनुभव से सीखे और कुछ लंबित मुद्दों पर अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन उसे इन्हें द्विपक्षीय संबंधों को विषाक्त नहीं बनाने देना चाहिए या भारत के साथ संबंधों के आड़े नहीं आने देना चाहिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठप्प होने के कगार पर है। यह कर्ज के जाल में फंस गया है और डिफॉल्ट बनने की ओर अग्रसर है। भारत के लिए व्यापार और संपर्क खोलना पाकिस्तान को अपने पैरों पर वापस लाने में मदद करेगा। इसमें वास्तव में कोई नकारात्मक पहलू नहीं है। कट्टरवाद और आतंकवाद जैसे अन्य मुद्दे आम चुनौतियां हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग इन्हें आतंकवाद के खतरे से छुटकारा पाने और कट्टरपंथ को हराने में सक्षम बनाएगा। इन दोनों ने खुद को बड़ी शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के विपरीत पक्षों में पाया है। लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो उनकी बातचीत करने की स्थिति काफी बढ़ जाएगी और वे बड़ी शक्ति की राजनीति के दबावों से प्रभावित होने का विरोध कर सकते हैं। भारत-पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बना कर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक-दूसरे के खिलाफ खंजर निकाले रखें। आर्थिक लाभ को कम करके नहीं आंका जा सकता। व्यापार मुद्रास्फीति से लडने, आवश्यक वस्तुओं की कमी को रोकने, दोनों पक्षों को बाजार और कनैक्टिविटी प्रदान करने और अब तक अवरुद्ध किए गए तालमेल को मुक्त करने में मदद करेगा। व्यापार और यात्रा संबंध न केवल राज्य बल्कि समाज की भौतिक और आर्थिक सुरक्षा को भी बढ़ाते हैं। एक-दूसरे को युद्ध के नजरिए से देखने की बजाय दोनों देश अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। विशेषकर

पाकिस्तान के मामले में, यह राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य से कल्याणकारी राज्य बनने की ओर बढ़ सकता है। वास्तव में सेना का प्रभाव घटनाओं के ऐसे मोड़ के लिए उत्प्रेरक होगा, क्योंकि भारत से कथित खतरा कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा। [4]

यदि भारत और पाकिस्तान एक उज्जवल भविष्य की दिशा में एक साथ काम कर सकते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अधिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। पाकिस्तान के लिए सहायक लाभ यह होगा कि सी.पी.ई.सी. पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच और मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक व्यवहार्य पुल होने के पाकिस्तान के सपने के बावजूद भी आगे की गति को देखेगा। कुछ पाकिस्तानी राजनेताओं, विशेष रूप से नवाज शरीफ ने इसे समझा। दुर्भाग्य से, उस समय पाकिस्तानी सेना इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि पाकिस्तानी सेना अब भारत के साथ मेल-मिलाप को बढ़ाने के लिए राजनेताओं से भी ज्यादा उत्सुक है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा द्वारा प्रतिपादित भू-अर्थशास्त्र की अवधारणा दृष्टिकोण के इस परिवर्तन को रेखांकित करती है।

ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सेना ने महसूस किया है कि शत्रुता की अंतहीन स्थिति पाकिस्तान को नीचे खींच रही है और अस्तित्व संबंधी समस्याएं पैदा कर रही है। अब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास करने का एक अवसर है। यदि वे इस अवसर का लाभ उठाते हैं तो यह न केवल दक्षिण एशिया का चेहरा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गतिशीलता को भी बदल सकता है, लेकिन अगर वे अवसर को बर्बाद करते हैं तो यह दुखद होगा, क्योंकि ऐसा अवसर कई-कई सालों तक खुद को पेश नहीं करेगा।[3]

निष्कर्ष

सन 2000 से लेकर 2018 तक भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हर मौके पर उन्हें और विश्व को सबूत पेश किये, जाने के उपरांत भी. पाकिस्तान द्वारा इन्हें रोकने की बजाय आतंकवाद को पोषण देकर हर तरह की सुविधा देने में जुटा हैं. हर मंच पर भारत की बात न सुनकर कश्मीर की राग अलापने से भारत पाक सम्बन्धों में कभी भी सुधार नही आ सकता.वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्वकप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत खेलने आई थी. इस दौरान भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सेमीफाइनल मैच के दौरान युसूफ रजा गिलानी और मनमोहन सिंह दोनों एक साथ बैठकर मैच का आनन्द ले रहे थे. क्रिकेट तथा परस्पर सांस्कृतिक व फिल्म जगत के कारण भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरे हैं.2016-17 में उरी, पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमलों तथा 2018 में आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के चलते आज फिर दोनों देशों के बिच तनातनी का माहौल बना हुआ हैं. कुलदीप जाधव मामला भी दोनों के राजनितिक/कुटनीतिक तथा राजनितिक संबंधो में भी खटास का कारण रहा हैं.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की हर संभव कोशिश की गईं, चाहे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को न्यौता हो या नवाज शरीफ के कार्यक्रम में मोदी का अचानक जाना, मोदी की ओर से उठाए गये, सकारात्मक कदमों में से हैं.दूसरी तरफ भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके यह जता दिया, हम दोस्त को दोस्ती निभाते हैं, दुश्मन के साथ दुश्मनी निभानी भी हमे आती हैं.भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच संघर्षविराम पर समझौते के कुछ दिन बाद भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामन्य रिश्ते चाहता है. नई दिल्ली ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मुद्दों को द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए. हालांकि, भारत ने साथ ही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई कमी नहीं आने वाली है.भारत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पिछले महीने ही दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा पर और अन्य क्षेत्रों में संघर्षविराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई.[2]

शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों का हल निकालने के लिए भारत प्रतिबद्ध

सीजफायर समझौते का पालन के बारे में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से कहा कि इस बारे में रक्षा मंत्रालय से जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा, 'भारत, पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामन्य रिश्ते चाहता है.'उन्होंने कहा कि भारत सभी मुद्दों, अगर कोई है, तो उसका शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान निकालने को प्रतिबद्ध है. महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने 2003 में संघर्षविराम समझौता किया था लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शायद ही इस पर अमल हुआ है. वहीं सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई या सीमा पर सैनिकों की तैनाता में कोई कमी नही की जाएगी.[9]

संदर्भ

[1] "सिंधु जल समझौते के उल्लंघन को 'युद्ध के लिए उकसाने' के तौर पर लिया जाएगा: पाकिस्तान". मूल से 28 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.

[2] "सिंधु जल संधि के मसले पर पाकिस्तान ने विश्व बैंक का रुख किया". मूल से 28 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.

[3] "पाकिस्तान पड़ा अलग-थलग - भारत के बाद तीन और देशों ने किया सार्क सम्मेलन में शिरकत से इंकार". एनडीटीवी खबर. मूल से 29 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.

[4] "पाकिस्तान को दिए 'सबसे तरजीही मुल्क' के दर्जे पर पुनर्विचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी". मूल से 28 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.

[5] "कल रात हमने LoC पर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल हमला किया: विदेश, रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में DGMO". एनडीटीवी खबर. मूल से 2 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.

[6] "भारत-पाक जंग हुई, तो खत्म हो जाएगी सभ्यता!". नवभारत टाईम्स. 11 दिसम्बर 2013. अभिगमन तिथि 12 दिसम्बर 2013

[7] बैरेट, स्कॉट, "संघर्ष और सहयोग के प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय जल संसाधन," नीति अनुसंधान काम कर कागज 1303, विश्व बैंक, मई 1994 है।

[8] मिशेल, Aloys आर्थर, सिंधु नदियों: एक अध्ययन के प्रभाव के विभाजन, येल यूनिवर्सिटी प्रेस: New Haven, 1967.

[9] वर्गीज, बी जी में, जल की उम्मीद है, और ऑक्सफोर्ड IBH प्रकाशन: नई दिल्ली, 1990.

International Journal of Trend in Scientific Research and Development
IJTSRD
International Journal of Trend in Scientific Research and Development
ISSN: 2456-6470